



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आषाढ़ 17, 1937

No. 241]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASADHA 17, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2015

सं. टीएएमपी/15/2011-केपीटी.- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार कांडला पत्तन न्यास की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए की वैधता की अवधि का विस्तार करती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/15/2011-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2015 के दूसरे दिन को पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए की वैधता अवधि का विस्तार करने से संबंधित है।

2. केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए को विगत में इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/15/2011-केपीटी दिनांक 9 अप्रैल, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था। उक्त आदेश को राजपत्र संख्या 118 द्वारा 4 मई 2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए का कार्यान्वयन 5 जुलाई 2010 से भूतलक्षी प्रभाव से किया गया था और पांच वर्षों के लिए अर्थात् 4 जुलाई, 2015 तक वैध था।

3.1. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 12 जून 2015 द्वारा यह उल्लेख किया है कि खारी भूमि के लिए पट्टा किराए से संबंधित प्रस्ताव भूमि आवंटन समिति को प्रस्तुत किया गया है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रस्ताव शीघ्र ही भेजा जाएगा। इस स्थिति को

देखते हुए, केपीटी ने इस प्राधिकरण से इस शर्त के साथ 6 महीनों की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 4 जनवरी 2016 तक विद्यमान दरों पर वसूली करना जारी रखने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है कि संशोधित दरों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रयोज्य बनाया जाएगा।

3.2. केपीटी ने खारी भूमि के लिए पट्टा किराए की वैधता अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध करते समय इस बात कोई उल्लेख नहीं किया है कि कब तक वह केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए के संशोधन से संबंधित अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तथापि, केपीटी ने यह सूचित किया है कि खारी भूमि के लिए पट्टा किराए के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव भूमि आवंटन समिति को प्रस्तुत किया गया है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव शीघ्र ही भेजा जाएगा। केपीटी द्वारा अवगत करायी गई उक्त स्थिति के आधार पर, केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए के संशोधन से संबंधित पत्तन को अपना प्रस्ताव 30 सितम्बर 2015 तक प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।

4.1. केपीटी की खारी भूमि के लिए विद्यमान पट्टा किराए की वैधता अवधि 4 जुलाई 2015 को समाप्त हो जाएगी। केपीटी ने केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए के संशोधन से संबंधित अपना प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। यदि केपीटी विनिर्धारित अवधि के भीतर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो भी इस प्राधिकरण को अंतिम रूप से विचार करने से पहले निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए परामर्श प्रक्रिया में समय तो लगेगा ही। यह प्राधिकरण, इसलिए, केपीटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर इसकी वैधता अवधि समाप्त होने की तारीख से 4 जनवरी 2016 तक अथवा केपीटी की खारी भूमि के संशोधित पट्टा किराए की अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, केपीटी की खारी भूमि के लिए विद्यमान पट्टा किराए की वैधता अवधि का विस्तार करता है।

4.2. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशा-निर्देश 2010 (जिसके आधार पर केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराया अप्रैल 2012 में निर्धारित किया गया है) में यह विनिर्दिष्ट है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराए में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि तब तक की जाती रहेगी जब तक इस प्राधिकरण द्वारा उन्हें संशोधित नहीं कर दिया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2012 में अनुमोदित आदेश में इस संबंध में एक विशिष्ट शर्त भी विनिर्धारित की गई है। चूंकि पट्टा किराए की विद्यमान अनुसूची में पहले से ही उस समय तक पट्टा किराए में 2% की दर से वार्षिक वृद्धि पहले से ही निर्धारित है, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दरों को संशोधित किया जाता है और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए की वैधता अवधि के विस्तार के दौरान 2% की वार्षिक वृद्धि लागू होना जारी रहेगी।

4.3. तथापि, इस संबंध में यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ विद्यमान पट्टा किराए का विस्तार केवल अनन्तिम व्यवस्था है ताकि वर्तमान परिदृश्य में रिक्तता को भरा जा सके। इस संबंध में केपीटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर केपीटी की खारी भूमि के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टा किराए भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे, जैसाकि केपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है।

5. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों को देखते हुए तथा समाहरण मनोनियोग के आधार पर यह प्राधिकरण केपीटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर केपीटी की खारी भूमि के लिए विद्यमान पट्टा किराए की वैधता अवधि का 4 जुलाई 2015 के पश्चात् 4 जनवरी 2016 तक अथवा इस संशोधित पट्टा किराए की अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ विस्तार करता है। केपीटी को यह निदेश दिया जाता है कि वह लागू भूमि नीति दिशा-निर्देश 2014 के अनुपालन में केपीटी की खारी भूमि के लिए पट्टा किराए के संशोधन से संबंधित अपना प्रस्ताव 30 सितम्बर 2015 तक हर हालत में प्रस्तुत कर दें।

टी.एस. बालासुब्रह्मनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2015 (127)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2015

No. TAMP/15/2011-KPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the lease rentals for salt lands of Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/15/2011-KPT

Kandla Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 2nd day of July, 2015)

This case relates to extension of the validity of lease rentals for salt lands of the Kandla Port Trust (KPT).

2. The lease rentals for salt lands of KPT was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/15/2011-KPT dated 9 April 2012. The said Order was notified in the Gazette of India on 4 May 2012 vide Gazette No.118. The lease rentals for the salt lands of KPT revised by this Authority were implementable with retrospective effect from 5 July 2010 and valid for five years, i.e. upto 4 July 2015.

3.1.The KPT vide its letter dated 12 June 2015 has stated that the proposal for revision of lease rentals for salt land has been submitted to the Land Allotment Committee and that the proposal will be sent shortly after seeking Board approval. In view of this position, the KPT has requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. upto 4 January 2016, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

3.2. The KPT while requesting for extension of the validity of the lease rentals for salt lands has not indicated the exact time by when it will file its proposal for revision of lease rentals for salt lands of KPT. The KPT has, however, reported that the proposal for revision of lease rentals for salt land has been submitted to Land Allotment Committee and that the proposal will be sent shortly after seeking Board approval. Based on the above status indicated by the KPT, the port is advised to file its proposal for revision of lease rentals for salt lands of KPT latest by 30 September 2015.

4.1.The validity of the existing lease rentals for salt lands of KPT will expire on 4 July 2015. The KPT has so far not filed its proposal for revision of lease rentals for salt lands of KPT. Even if the KPT file its proposal within stipulated time, it will take time for the consultation process to conclude before final consideration of this Authority. This Authority, therefore, extends the validity of the existing lease rentals for salt lands of KPT from the date of its expiry till 4 January 2016 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals of salt lands of KPT based on the tariff proposal to be filed by the KPT, whichever is earlier.

4.2. Further, the Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the lease rentals for salt lands of KPT has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. Since the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the Competent Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the lease rentals for salt lands of KPT.

4.3. However, in this regard, it is relevant here to mention that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the salt land of KPT based on a proposal to be filed by the KPT in this regard may have retrospective effect, as requested by the KPT.

5. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing lease rentals for salt lands of KPT, beyond 4 July 2015 upto 4 January 2016 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the KPT, whichever is earlier, with an annual escalation of 2%. The KPT is directed to file its proposal for revision of lease rents for salt lands of KPT positively by 30 September 2015 following the applicable Land Policy Guidelines, 2014.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2015/(127)]